5

केन्ज़ का रोज़गार सिद्धान्त

(KEYNESIAN THEORY OF EMPLOYMENT)

◆1. केन्ज़ का रोज़गार सिद्धान्त क्या है? (What is Keynesian Theory of Employment ?)

बीसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री **लार्ड जे० एम० केन्ज़** ने अपनी पुस्तक 'The General Theory of Employment, Interest and Money' (1936) में रोज़गार के आधुनिक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। **लार्ड केन्ज़** के अनुसार एक पूँजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोज़गार की स्थिति सामान्य स्थिति नहीं है। वास्तव में हर अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी पाई जा सकती है। **लार्ड केन्ज़** के ये विचार 1930 की महामंदी के अनुभव पर आधारित थे। सन् 1930 में लगभग सभी पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में महामंदी के कारण बेरोज़गारी में बहुत वृद्धि हुई थी। बेरोज़गारी का मुख्य कारण कुल पूर्ति की तुलना में कुल माँग में होने वाली कमी थी। कई देशों जैसे-अमेरिका, फ्रांस आदि ने बेरोज़गारी को दूर करने के लिए परंपरावादी रोज़गार सिद्धान्त द्वारा प्रतिपादित उपायों जैसे नकद मजदूरी में कटौती, ब्याज में कमी आदि को अपनाया। परन्तु इन उपायों द्वारा बेरोज़गारी दूर करने में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। **लार्ड केन्ज़** ने बेरोज़गारी की इस समस्या का वास्तविक विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला कि बेरोज़गारी का मुख्य कारण प्रभावपूर्ण माँग में होने वाली कमी है। प्रभावपूर्ण माँग कुल माँग का वह स्तर है जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होती है। इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया था कि **प्रभावपूर्ण माँग** (Effective Demand) को बढ़ाकर बेरोज़गारी को दूर किया जा सकता है। कुल माँग में दो **प्रकार की** माँग शामिल होती है। (1) **उपभोग वस्तुओं की माँग** (Consumption) तथा (2) **पूँजीगत वस्तुओं की माँग** (Investment)। अल्पकाल में उपभोग लगभग स्थिर रहता है। इसलिए प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि मुख्य रूप से निवेश में वृद्धि करके की **जा सकती है**। मंदी के दिनों में लाभ की संभावना कम होती है। इसलिए निजी क्षेत्र निवेश को अधिक नहीं बढ़ाएगा। अतएव् पूर्ण रोज़गार के **लक्ष्य को** प्राप्त करने के लिए यह कार्य सरकार को करना पड़ेगा। **लार्ड केन्ज़** का यह विचार था कि बेरोज़गारी को दूर करके पूर्ण रोज़गार **की स्थिति** को प्राप्त करने के लिए **सरकारी हस्तक्षेप** (Government Interference) आवश्यक है। **लार्ड केन्ज़** से पूर्व प्रसिद्ध परंपरावादी अर्थशास्त्री **माल्थस** (R.T. Malthus) ने भी यह मत प्रस्तुत किया था कि रोज़गार में कमी होने का मुख्य कारण प्रभावपूर्ण माँग में होने वाली कमी है। लेकिन माल्थस यह नहीं बता सके कि प्रभावपूर्ण माँग में कमी क्यों होती है।

◆2. मान्यताएँ (Assumptions)

लार्ड केन्ज़ द्वारा प्रतिपादित रोज़गार का सिद्धान्त निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है:

(1) अल्पकाल (Short Period): **केन्ज़** का रोज़गार सिद्धान्त अल्पकाल में लागू होता है। लार्ड **केन्ज़** की यह मान्यता थी कि विकसित देशों में बेरोज़गारी की समस्या एक अल्पकालीन समस्या है क्योंकि, **"दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं।"** (In the long run we are all dead.) अल्पकाल में कुल पूर्ति स्थिर रहती है। अतएव कुल माँग में वृद्धि करके ही बेरोज़गारी को दूर करके रोज़गार **की** मात्रा को बढ़ाया जा सकता है।

(2) पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect Competition): **केन्ज़** का रोज़गार सिद्धान्त भी परंपरावादी सिद्धान्त के समान पूर्ण प्रतियोगिता **की मान्यता** पर आधारित है।

(3) बन्द अर्थव्यवस्था (Closed Economy): **केन्ज़** के रोज़गार सिद्धान्त की यह मान्यता है कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था बन्द अर्थव्यवस्था होती है जिसमें रोज़गार तथा आय के स्तर पर विदेशी व्यापार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(4) सरकारी आय तथा व्यय की उपेक्षा (Ignores the role of Government as a Spender or a Taxer): केन्ज़ का सामान्य सिद्धान्त इस बात की उपेक्षा करता है कि सरकार का कोई **कार्य कर अधिकारी** (Taxer) या **व्ययकर्ता** (Spender) के रूप में है। **केन्ज़** ने कुल माँग पर सरकारी क्षेत्र के पड़ने वाले प्रभाव की अवहेलना की है।

(5) घटती सीमान्त उत्पादकता (Diminishing Marginal Productivity): **केन्ज़** के रोज़गार सिद्धान्त की एक मान्यता यह भी है कि जैसे-जैसे श्रम की अधिक इकाइयों को रोज़गार प्रदान किया जाता। उनकी सीमान्त उत्पादकता कम होती जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन पर **घटते सीमान्त प्रतिफल का नियम** (Law of Diminishing Marginal Returns) लागू होता है।

(6) केवल श्रम ही उत्पादन का घटता-बढ़ता साधन है (Labour is the only Variable Factor of Production): **केन्ज़** के सिद्धान्त की यह भी मान्यता है कि अल्पकाल में केवल श्रम ही उत्पादन का घटता-बढ़ता साधन है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करने से उत्पादन में वृद्धि होती है।

(7) श्रमिकों में मुद्रा भ्रान्ति है (Labour has Money Illusion): **केन्ज़** के रोज़गार सिद्धान्त की एक मान्यता यह भी है कि श्रमिकों में इस संबंध में गलतफहमी है कि मुद्रा की कीमत स्थिर रहती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि श्रमिक यह मानते हैं कि नकद मजदूरी जिस अनुपात में बढ़ेगी वास्तविक मजदूरी भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। श्रमिक कीमत में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की अवहेलना करता है।

(8) मुद्रा द्वारा मूल्य का संचय भी किया जाता है (Money also acts as a Store of Value): **केन्ज़** के सिद्धान्त की यह भी मान्यता है कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य ही नहीं करती बल्कि इसके द्वारा मूल्य का संचय भी किया जाता है।

(9) समय विलम्ब की उपेक्षा (No Time Lag): **केन्ज़** के सिद्धान्त की यह मान्यता है कि विभिन्न आर्थिक तत्त्वों में समन्वय (Adjustment) बिना किसी विलम्ब के होता है। आय में जिस अवधि में वृद्धि होती है उपभोग तथा निवेश में उसी अवधि में परिवर्तन आ जाता है।

(10) अपूर्ण रोज़गार संतुलन (Under employment Equilibrium): **केन्ज़** के रोज़गार सिद्धान्त की एक मान्यता यह भी है कि संतुलन की स्थिति अपूर्ण रोज़गार की अवस्था में भी संभव है।

(11) बचत तथा निवेश फलन (Saving and Investment Function): **केन्ज़** का रोज़गार सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि बचत आय पर निर्भर करती है अर्थात् $S = f(Y)$। इसके विपरीत निवेश ब्याज की दर पर निर्भर करता है अर्थात् $I = f(r)$।

(12) ब्याज मौद्रिक तत्त्वों पर निर्भर करता है (Interest is a Monetary Phenomenon): **केन्ज़** के सिद्धान्त की यह भी मान्यता है कि ब्याज का निर्धारण मौद्रिक तत्वों अर्थात् मुद्रा की माँग **तथा पूर्ति पर निर्भर करता है।** मुद्रा की माँग, **तरलता अधिमान** (Liquidity Preference) द्वारा प्रकट की जाती है। तरलता अधिमान लेन-देन, सावधानी तथा सट्टा उद्देश्यों पर निर्भर करता है।

◆3. केन्ज़ के सिद्धान्त की व्याख्या (Explanation of Keynesian Theory)

लॉर्ड **केन्ज़** के रोज़गार सिद्धान्त के अनुसार पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में कुल उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय रोज़गार के स्तर पर निर्भर करती है क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधन **जैसे पूँजी**, तकनीक आदि स्थिर रहते हैं। रोज़गार का स्तर प्रभावपूर्ण माँग पर निर्भर करता है। **प्रभावपूर्ण माँग** (Effective Demand) **कुल माँग के उस स्तर को कहते हैं जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होती है।** अतएव **एक्ले गार्डनर** के अनुसार **केन्ज़** के सिद्धान्त का आधारभूत विचार यह है कि किसी देश में रोज़गार का स्तर कुल माँग तथा कुल पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। **प्रभावपूर्ण माँग** (Effective Demand) कुल माँग तथा कुल पूर्ति के संतुलन को प्रकट करती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कुल माँग के केवल उस स्तर को प्रभावपूर्ण माँग कहा जायेगा जिस पर वह देश में की जाने वाली कुल पूर्ति के बराबर हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी देश के एक लाख लोगों को रोज़गार पर लगाने से यदि एक निश्चित

समय मे कुल पूर्ति कीमत 100 करोड़ रुपये है तथा समय की उसी अवधि में कुल माँग कीमत भी 100 करोड़ रुपये है तो उस स्थिति में कुल माँग कीमत कुल पूर्ति कीमत के बराबर होगी। अतएव 100 करोड़ की कुल माँग कीमत को प्रभावपूर्ण माँग कहा जायेगा।

$$\boxed{Y = f(N)}$$

(राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन (Y) रोज़गार के स्तर (N) पर निर्भर करता है।)

$$\boxed{N = f(ED)}$$

(रोज़गार का स्तर (N) प्रभावपूर्ण माँग (ED) पर निर्भर करता है।

$$\boxed{ED \rightarrow (AD = AS)}$$

(प्रभावपूर्ण माँग (ED) कुल माँग (AD) तथा कुल पूर्ति (AS) की समानता को दर्शाती है।)

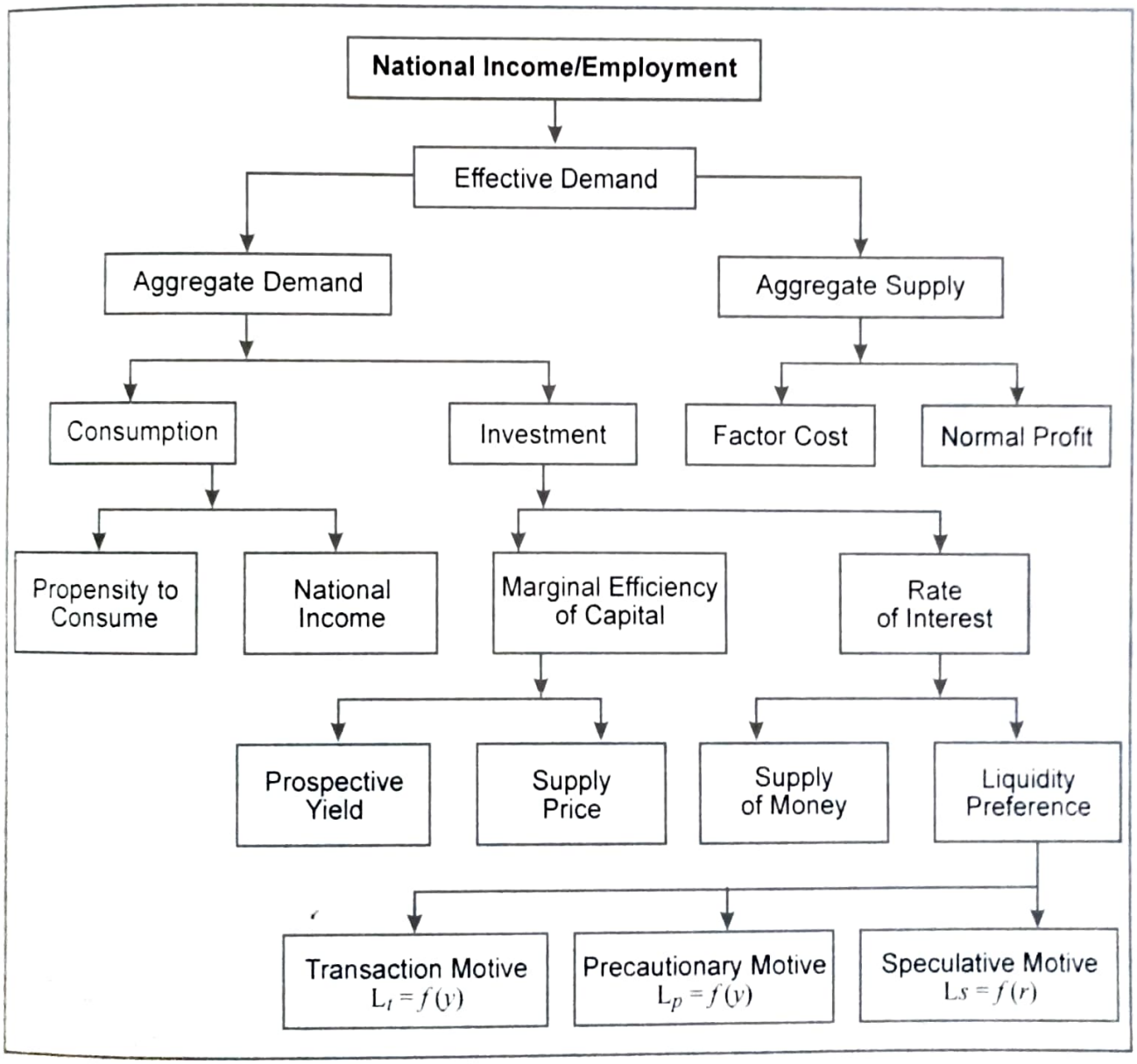

दिये गए चित्र के आधार पर केन्ज़ के सिद्धान्त रोज़गार की व्याख्या निम्नलिखित ढंग से की जा सकती है:

(1) राष्ट्रीय आय की मात्रा रोजगार की माँग पर निर्भर करती है।

(2) रोज़गार की मात्रा **प्रभावपूर्ण माँग** (ED) पर निर्भर करती है। प्रभावपूर्ण माँग कुल माँग का वह स्तर है जो कुल पूर्ति के बराबर होता है।

(3) **प्रभावपूर्ण माँग** कुल माँग तथा पूर्ति पर निर्भर करती है। कुल माँग के उस स्तर को प्रभावपूर्ण माँग कहते हैं जिस पर कुल माँग कीमत तथा कुल पूर्ति कीमत बराबर होती है।

(4) कुल पूर्ति (Aggregate Supply): कुल पूर्ति की धारणा को समझने के लिए **कुल पूर्ति कीमत** (Aggregate Supply Price) तथा **कुल पूर्ति तालिका** (Aggregate Supply Schedule) या **कुल पूर्ति** के अंतर को समझना आवश्यक है। **कुल पूर्ति कीमत** (Aggregate Supply Price) से अभिप्राय उस कुल रकम से है जो सभी उत्पादकों को रोज़गार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादित किए गए उत्पादन की मात्रा को बेचने से अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में कुल पूर्ति, उत्पादन की कुल लागत के बराबर होती है। इसे **राष्ट्रीय आय** भी कहा जा सकता है। इसके विपरीत कुल पूर्ति तालिका या कुल पूर्ति से अभिप्राय उस तालिका से है जो रोज़गार के विभिन्न स्तरों पर मिलने वाली कुल पूर्ति कीमत को प्रकट करती है। अल्पकाल में कुल पूर्ति कीमत स्थिर रहती है।

(5) कुल माँग (Aggregate Demand): माँग की धारणा को समझने के लिए **कुल माँग कीमत** (Aggregate Demand Price) तथा **कुल माँग तालिका** (Aggregate Demand Schedule) के अंतर को समझना भी आवश्यक है। **कुल माँग कीमत** से अभिप्राय उस कुल रकम से है जो सभी उत्पादकों को रोज़गार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादित किये गये उत्पादन की मात्रा को बेचने से प्राप्त होने की संभावना होती है। उसके विपरीत कुल माँग तालिका या कुल माँग से अभिप्राय उस तालिका से है जो रोज़गार के विभिन्न स्तरों पर मिलने वाली कुल माँग कीमत को प्रकट करती है।

केन्ज़ के अनुसार कुल माँग को दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, **(a) उपभोग** (Consumption) तथा **(b) निवेश** (Investment) अर्थात्

$$\mathbf{AD = C + I}$$

(a) उपभोग व्यय (Consumption Expenditure): उपभोग वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है उसे उपभोग कहा जाता है। उपभोग व्यय कुल माँग का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। उपभोग व्यय में वृद्धि होने से कुल आय में वृद्धि होती है। उपभोग व्यय मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। (i) **उपभोग प्रवृत्ति** तथा (ii) **राष्ट्रीय आय।**

(i) उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume): उपभोग प्रवृत्ति आय के विभिन्न स्तरों पर किये जाने वाले उपभोग व्यय को प्रकट करती है। यह दो प्रकार की होती है। **(a) औसत उपभोग प्रवृत्ति** (Average Propensity to Consume): औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग व्यय तथा आय का अनुपात है इसका अनुमान कुल उपभोग व्यय को कुल आय से भाग देने पर लगाया जा सकता है अर्थात् $APC = \frac{C}{Y}$। **औसत उपभोग प्रवृत्ति द्वारा कुल माँग में कुल उपभोग का भाग ज्ञात हो** जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि संतुलन की स्थिति में कुल आय ₹ 100 करोड़ है तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC) 60 प्रतिशत है तो इससे ज्ञात होगा कि उपभोग आय = ₹ 0.60 करोड़ है। (b) **सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति** (Marginal Propensity to Consume): सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। इसका अनुमान कुल उपभोग में होने वाले परिवर्तन को कुल आय में होने वाले परिवर्तन की मात्रा से भाग देकर लगाया जाता है अर्थात् $MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$। मान लो आय ₹ 100

करोड़ से बढ़कर ₹ 120 करोड़ हो जाती है तथा उपभोग व्यय ₹ 60 करोड़ से बढ़कर ₹ 70 करोड़ हो जाता है। आय में होने वाला परिवर्तन ΔY = ₹ 120 करोड़ – ₹ 100 करोड़ = ₹ 20 करोड़ तथा उपभोग में होने वाला परिवर्तन ΔC = ₹ 70 रुपये – ₹ 60 करोड़ = ₹ 10 करोड़ रुपये है। अतएव सीमांत उपभोग प्रवृत्ति $MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$ होगी। **सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति से ज्ञात होता है कि उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होने से कुल उपभोग व्यय में कितनी वृद्धि होगी।**

(ii) राष्ट्रीय आय का आकार (Size of National Income): केन्ज़ की यह मान्यता है कि उपभोग आय का फलन है (Consumption is a function of Income) अर्थात् $C = f(Y)$।

आय में वृद्धि होने से उपभोग में वृद्धि होती है। परन्तु उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि के अनुपात में कम होती है। इससे सिद्ध होता है कि जब राष्ट्रीय आय अथवा कुल पूर्ति में वृद्धि होती है तो कुल उपभोग में राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि होने के कारण कुल माँग, कुल पूर्ति की तुलना में कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप फर्में उत्पादन कम कर देती हैं तथा बेरोज़गारी फैलती है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुल माँग में वृद्धि की जानी चाहिए। कुल माँग में वृद्धि करने के लिए कुल उपभोग व्यय में वृद्धि करना संभव नहीं है क्योंकि कुल उपभोग कई ऐसे भावगत (Subjective) तत्त्वों जैसे रुचि, फैशन, आदत तथा वस्तुगत (Objective) तत्त्वों जैसे आय का वितरण आदि पर निर्भर करता है जो अल्पकाल में स्थिर रहते हैं। अतएव केन्ज़ के रोज़गार सिद्धान्त के अनुसार कुल माँग को निवेश में वृद्धि करके बढ़ाने की संभावनाएं अधिक हैं।

(b) निवेश (Investment): पूँजीगत वस्तुओं जैसे मशीनों पर जो व्यय किया जाता है उसे निवेश कहते हैं। निवेश से अभिप्राय उन खर्चों से है जिनके द्वारा पूँजी में वृद्धि होती है। निवेश कुल माँग का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण भाग है। निवेश के बढ़ने से **गुणांक** (Multiplier) प्रभाव के फलस्वरूप आय में कई गुणा अधिक वृद्धि होती है तथा रोज़गार काफी मात्रा में बढ़ता है। केन्ज़ के अनुसार निवेश मुख्य रूप से दो तत्त्वों पर निर्भर करता है - (1) **ब्याज की दर** (2) **पूँजी की सीमान्त उत्पादकता।**

(i) ब्याज की दर (Rate of Interest): केन्ज़ के अनुसार ब्याज की दर में कमी होने से निवेश बढ़ता है, तथा ब्याज की दर बढ़ने पर निवेश कम होता है। ब्याज की दर मुद्रा की माँग तथा मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करती है। मुद्रा की माँग, तरलता अधिमान (Liquidity Preference) पर निर्भर करती है। तरलता अधिमान से अभिप्राय यह है कि लोग मुद्रा को तीन उद्देश्यों से नकदी के रूप में रखना चाहते हैं। ये तीन उद्देश्य हैं - (i) **लेन-देन उद्देश्य** (Transaction Motive), (ii) **सावधानी उद्देश्य** (Precautionary Motive) तथा (iii) **सट्टा उद्देश्य** (Speculative Motive)।

(ii) पूँजी की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Efficiency of Capital): पूँजी की सीमान्त उत्पादकता से अभिप्राय लाभ की दर से है। पूँजी की एक अतिरिक्त इकाई के लगाने से कुल लाभ में जो वृद्धि होती है उसे पूँजी की सीमान्त उत्पादकता कहा जाता है। पूँजी की सीमान्त उत्पादकता दो तत्त्वों पर निर्भर करती है - (a) **अनुमानित आय** (Prospective Yield): पूँजी की एक इकाई से उसके कार्यकाल की कुल अवधि में जितनी आय मिलने की संभावना होती है उसे अनुमानित आय कहते हैं। **(b) पूर्ति कीमत** (Supply Price): पूर्ति कीमत से अभिप्राय किसी मशीन की उस कीमत से है जो उसी प्रकार की एक नई मशीन के लिए देनी पड़ेगी। एक उत्पादक निवेश करते समय ब्याज की दर तथा पूँजी की सीमान्त उत्पादकता की तुलना करता जाता है। यदि पूँजी की सीमान्त उत्पादकता ब्याज की दर से अधिक है तो निवेश किया जाएगा। इसके विपरीत यदि पूँजी की सीमान्त उत्पादकता ब्याज की दर से कम है तो निवेश नहीं किया जाएगा। यदि दोनों बराबर हैं तो निर्धारित करना कठिन होगा कि निवेश किया जाए अथवा नहीं किया जाए।

संक्षेप में, **उपरोक्त विवरण से सिद्ध हो जाता है कि केन्ज़ द्वारा दिए गए रोज़गार सिद्धान्त के अनुसार विकसित पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में बेरोज़गारी पाई जा सकती है। इस बेरोज़गारी का मुख्य कारण प्रभावपूर्ण माँग में होने वाली कमी है। प्रभावपूर्ण माँग उपभोग तथा निवेश पर निर्भर करती है। अल्पकाल में उपभोग पर किये जाने वाला व्यय**

साधारणतया स्थिर रहता है। अतएव निवेश में वृद्धि करके कुल माँग को बढ़ाने की संभावनाएं अधिक हैं। इसके फलस्वरूप आय तथा रोज़गार में वृद्धि होगी।

◆4. रोज़गार का निर्धारण (Determination of Employment)

पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में रोज़गार का निर्धारण कुल माँग के उस स्तर पर होगा जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होती है। इस स्तर को **संतुलन का स्तर अथवा प्रभावपूर्ण माँग** (Effective Demand) कहा जाता है। **केन्ज़** के अनुसार, **''रोज़गार का स्तर वहाँ पर तय होता है जहां कुल माँग फंक्शन तथा कुल पूर्ति फंक्शन एक-दूसरे को काटते हैं।''** (The volume of Employment is given by the point of intersection between the Aggregate Demand function and Aggregate Supply function. - **Keynes**)।

अल्पकाल में कुल पूर्ति स्थिर रहती है अतएव् **कुल माँग में परिवर्तन करके प्रभावपूर्ण माँग तथा रोज़गार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है।** एक बन्द अर्थव्यवस्था में कुल माँग **उपभोग तथा निवेश पर निर्भर करती है। उपभोग, राष्ट्रीय आय तथा उपभोग प्रवृत्ति** पर निर्भर करती है। उपभोग प्रवृत्ति **कई भावगत** (Subjective) **तथा वस्तुगत** (Objective) तत्त्वों पर निर्भर करती है जो अल्पकाल में स्थिर रहता है। इसलिए अल्पकाल में उपभोग की मात्रा को बढ़ाना संभव नहीं होता। कुल मांग का दूसरा निर्धारक तत्त्व निवेश है। **निवेश, ब्याज की दर तथा पूँजी की सीमान्त उत्पादकता** पर निर्भर करती है। ब्याज की दर, मुद्रा की माँग तथा मुद्रा की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। मुद्रा की माँग **तरलता अधिमान** (Liquidity Preference) के लिए की जाती है। तरलता अधिमान से अभिप्राय है सम्पत्ति को मुद्रा या नकद के रूप में रखना। लोग अपनी सम्पत्ति को नकदी के रूप में तीन उद्देश्यों के लिए रखते हैं। ये उद्देश्य हैं: **(1) लेन-देन उद्देश्य, (2) सावधानी उद्देश्य तथा (3) सट्टा उद्देश्य**। लेन-देन उद्देश्य तथा सावधानी उद्देश्य आय पर निर्भर करते हैं जबकि सट्टा उद्देश्य ब्याज की दर पर निर्भर करता है। लोग ब्याज की ऊंची दर पर अधिक ऋण देने को तैयार होंगे तथा नीची दर पर कम ऋण देना चाहेंगे। **पूँजी की सीमान्त उत्पादकता** (Marginal Efficiency of Capital) वास्तव में लाभ की दर को व्यक्त करती है। यह भी दो तत्त्वों पर निर्भर करती है। एक **पूर्ति कीमत** (Supply Price) तथा दूसरे **अनुमानित आय** (Prospective Yield)। एक निवेशकर्ता निवेश करते समय ब्याज की दर तथा पूँजी की सीमान्त उत्पादकता की तुलना करता जाता है। जब पूँजी की सीमान्त उत्पादकता (MEC) ब्याज की दर से कम होती है तो निवेश नहीं करता। अल्पकाल में ब्याज की दर को कम करके निवेश में वृद्धि की जा सकती है। यदि निजी क्षेत्र निवेश कम करता है तो सरकार स्वयं निवेश करके निवेश की मात्रा को बढ़ा सकती है। अतएव् **केन्ज़** के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार यदि किसी देश में बेरोजगारी हो तो इसे दूर करने के लिए प्रभावपूर्ण माँग को बढ़ाना चाहिये। **प्रभावपूर्ण माँग** को बढ़ाने के लिए कुल माँग में वृद्धि की जानी चाहिए। कुल माँग में वृद्धि करने के लिए उपभोग तथा निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए। परन्तु अल्पकाल में उपभोग स्थिर रहता है इसलिए निवेश में वृद्धि करके ही कुल माँग को बढ़ाया जा सकता है। इसके फलस्वरूप रोज़गार में वृद्धि होगी। केन्ज़ का यह विचार था कि निवेश में वृद्धि होने के फलस्वरूप **गुणक प्रभाव** (Multiplier Effect) के कारण आय तथा रोजगार में कई गुणा अधिक वृद्धि होगी। संक्षेप में, **प्रभावपूर्ण माँग अर्थात् निवेश को बढ़ाकर बेरोजगारी को दूर करके पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।** रोज़गार के स्तर के निर्धारण को तालिका 1 तथा चित्र 1 के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

तालिका 1. रोजगार का निर्धारण (Determination of Employment)

Employment (N) (In lakhs)	Aggregate Supply (₹ crore)	Aggregate Demand (₹ crore)	Trends in Employment
0	0	60	Rise
10	60	100	Rise
20	90	120	Rise
30	120	140	Rise
40	150	160	Rise
50	180	180	Equilibrium
60	210	190	Fall
70	240	200	Fall

उपरोक्त तालिका 1 से ज्ञात होता है कि:

(1) जब रोज़गार की मात्रा शून्य है तो भी कुल माँग ₹ 60 करोड़ है तथा कुल पूर्ति शून्य है। इसका कारण यह है कि बेरोज़गार व्यक्ति भी उपभोग पर कुछ न कुछ खर्च अवश्य ही करता है।

(2) रोज़गार की 40 लाख संख्या तक कुल पूर्ति के साथ-साथ कुल माँग बढ़ रही है। परन्तु कुल माँग कुल पूर्ति से अधिक है। इसलिए उत्पादक अधिक उत्पादन करेंगे। इसके फलस्वरूप अधिक श्रमिकों को रोज़गार प्राप्त होगा।

(3) रोज़गार की 50 लाख संख्या पर कुल पूर्ति कुल माँग के बराबर है अर्थात् ₹ 180 करोड़ है। यह संतुलन की स्थिति होगी। **अर्थव्यवस्था में रोज़गार की संतुलन मात्रा यहीं पर निर्धारित होगी।** परन्तु इस अर्थव्यवस्था में 70 लाख श्रमिक रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं। अत: संतुलन की इस स्थिति में भी 20 लाख लोग बेरोज़गार रह जायेंगे। इससे सिद्ध होता है कि संतुलन की स्थिति बेरोज़गारी की स्थिति में भी संभव है। इस संतुलन को केन्ज़ ने **अल्प रोज़गार संतुलन** (Under-Employment Equilibrium) की संज्ञा दी है।

(4) रोज़गार की 50 लाख संख्या के पश्चात् जैसे-जैसे अधिक श्रमिकों को रोज़गार दिया जा रहा है कुल माँग कुल पूर्ति से कम होती जाती है। इसलिए उत्पादक 50 लाख श्रमिकों से अधिक श्रमिकों को रोज़गार देना पसन्द नहीं करेंगे।

अतएव ऊपर दी गई तालिका 1 से ज्ञात होता है कि रोज़गार का संतुलन वहीं पर निर्धारित होगा जहां कुल माँग व कुल पूर्ति एक-दूसरे के बराबर हैं।

चित्र 1 में OX अक्ष पर रोज़गार तथा OY अक्ष पर **अनुमानित प्राप्तियां** (Excepted Receipts) को प्रकट किया गया है। AS कुल पूर्ति वक्र है। AD कुल माँग वक्र है। इस चित्र के E बिंदु से ज्ञात होता है कि रोज़गार की 50 लाख संख्या पर कुल पूर्ति तथा कुल माँग वक्र एक-दूसरे के बराबर हैं, **अत: बिंदु E संतुलन बिंदु** है। यदि रोज़गार की संख्या कम होकर 40 लाख हो जाए, तो जैसा बिंदु D से ज्ञात होता है कुल माँग ₹ 160 करोड़ होगी तथा कुल पूर्ति जैसा बिंदु A से ज्ञात है ₹ 150 करोड़ होगी। अतएव् कुल माँग, कुल पूर्ति से AD अधिक होगी। कुल माँग के अधिक होने के कारण उत्पादक उत्पादन में वृद्धि करेंगे। इसके फलस्वरूप रोज़गार की संख्या तब तक बढ़ती जाएगी जब तक रोज़गार बढ़कर 50 लाख नहीं हो जाता। रोज़गार के

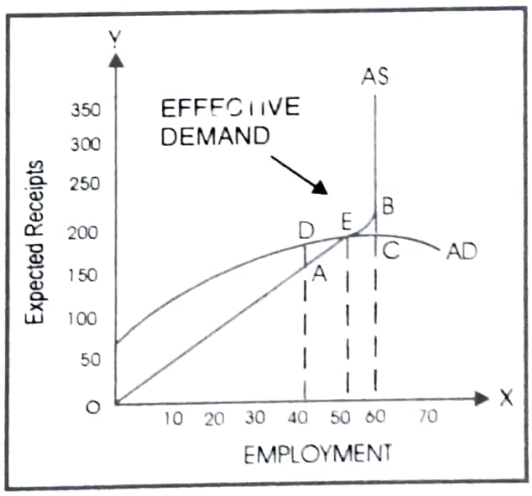

चित्र 1

इस स्तर पर कुल माँग तथा कुल पूर्ति एक-दूसरे के बराबर होंगे अतएव यह संतुलन की स्थिति होगी। यदि रोज़गार का स्तर बढ़कर 60 लाख हो जाता है तो कुल माँग जैसा बिंदु C से ज्ञात होता है ₹ 190 करोड़ होगी। जबकि कुल पूर्ति ₹ 210 करोड़ होगी जैसा कि बिंदु B से ज्ञात होता है अतएव कुल माँग कुल पूर्ति से कम होगी, उत्पादकों को हानि होगी। वे उत्पादन कम करेंगे। उत्पादन कम होने के फलस्वरूप रोज़गार कम होगा। रोज़गार का स्तर दोबारा संतुलन स्तर अर्थात् 50 लाख पर पहुंच जाएगा।

◆ 5. पूर्ण रोज़गार की प्राप्ति (Achievement of Full Employment)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि एक अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी की स्थिति में भी संतुलन की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इसे **अल्प रोज़गार संतुलन** (Under-Employment Equilibrium) कहते हैं। अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली बेरोज़गारी को दूर करके **पूर्ण रोज़गार** (Full Employment) की स्थिति प्राप्त करने के लिए कुल माँग में वृद्धि की जानी आवश्यक है। केन्ज़ के अनुसार अल्पकाल में कुल माँग में वृद्धि करने के लिए निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए। क्योंकि अल्पकाल में उपभोग व्यय स्थिर रहता है। निवेश में वृद्धि होने के फलस्वरूप कुल माँग में वृद्धि होगी। अतएव माँग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगी। यह नई माँग वक्र पूर्ति वक्र को पूर्ण रोज़गार के स्तर पर काटेगी। अतएव इस स्थिति में जो संतुलन स्थापित होगा उसे पूर्ण रोज़गार संतुलन कहा जाएगा। पूर्ण रोज़गार संतुलन की स्थिति को चित्र 2 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र 2 से ज्ञात होता है कि जब माँग वक्र AD है तो अर्थव्यवस्था बिंदु E पर संतुलन की अवस्था में होगी। बिंदु E पर कुल माँग वक्र AD कुल पूर्ति वक्र AS को काट रही है। संतुलन की इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में YY_1 लाख लोग बेरोज़गार हैं, क्योंकि OY_1 श्रमिक रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं जबकि रोज़गार OY श्रमिकों को प्राप्त हो रहा है। अत: **इसे अल्प बेरोज़गार संतुलन** (Under Employment Equilibrium) की स्थिति कहा जाएगा। यदि निवेश में वृद्धि होने के फलस्वरूप कुल माँग में वृद्धि हो जाती है तो कुल माँग वक्र ऊपर की ओर खिसक कर AD_1 हो जाएगी। यह माँग वक्र AD_1 पूर्ति वक्र AS को F बिंदु पर काटेगी। अतएव संतुलन की नई स्थिति बिंदु F द्वारा प्रकट होगी। संतुलन की इस स्थिति में सभी OY_1 श्रमिकों को रोज़गार प्राप्त हो जायेगा। अतएव संतुलन की यह स्थिति **पूर्ण रोज़गार संतुलन** (Full Employment) को प्रकट करेगी। यदि निवेश में और अधिक वृद्धि होगी तो कुल माँग में भी वृद्धि होगी। कुल माँग वक्र ऊपर की ओर खिसककर AD_2 हो जायेगी। यह नई माँग वक्र कुल पूर्ति वक्र AS को बिंदु P पर काटेगी। अतएव संतुलन स्थिति P बिंदु द्वारा प्रकट होगी। इस स्थिति में रोज़गार तथा उत्पादन की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हो सकेगी क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले से ही पूर्ण रोज़गार के स्तर को प्राप्त कर चुकी है। इस स्थिति में कुल माँग बढ़ने के फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि होगी। इस स्थिति को **अति रोज़गार** (Over Employment) की अवस्था कहते हैं।

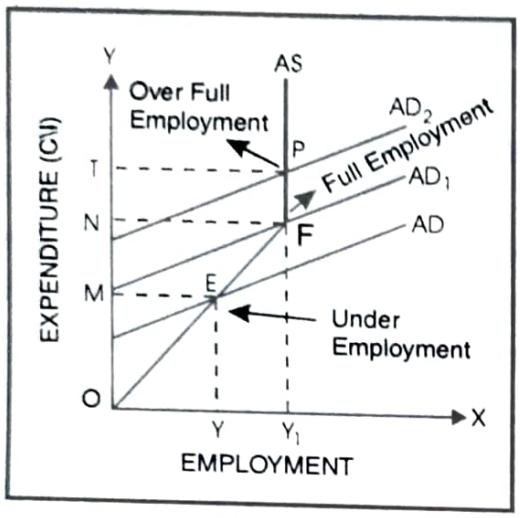

चित्र 2

◆5.1 आय या उत्पाद का निर्धारण (Determination of Income or Output)

केन्ज के अनुसार आय या उत्पाद रोज़गार के स्तर पर निर्भर करता है। आय या उत्पाद का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र की सहायता से किया जा सकता है:

$$Y = C + I$$

$$C = C_o + bY$$

$$I = \bar{I}$$

$$\boxed{Y = C_o + bY + \bar{I}}$$

(यहाँ Y = आय; C = उपभोग; I = निवेश ; Co = स्वतंत्र उपभोग; b = सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति या $\frac{\Delta C}{\Delta Y}$, Y = आय

$\bar{I}$= स्वतंत्र निवेश)

मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक अवस्था में निम्नलिखित स्थिति है :

$$Y = 0$$

$$C_o = ₹\ 25 \text{ करोड़}$$

$$b = 0.75$$

$$\bar{I} = ₹\ 75 \text{ करोड़}$$

यदि प्रारम्भ में कोई आय नहीं हो रही तो लोग पिछली बचत को ही उपयोग तथा निवेश पर व्यय कर रहे हैं तो आय का निर्धारण उपरोक्त सूत्र के आधार पर निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है:

$$Y = 25 + (0.75 \times 0) + 75 = ₹\ 100$$

जब आय बढ़कर ₹ 100 करोड़ हो गई तथा स्वतंत्र निवेश ₹ 75 करोड़ का जारी रहा तो दूसरी अवस्था में आय बढ़कर निम्नलिखित स्तर पर पहुंच जायेगी:

$$Y = 25 + 0.75 \times 100 + 75$$

$$= 25 + \frac{3}{4} \times 100 + 75 = ₹\ 175 \text{ करोड़}$$

इस स्थिति में उपभोग ₹ 100 करोड़ होगा। आय विस्तार की तीसरी अवस्था में आय का अनुमान निम्नलिखित ढंग से लगाया जा सकता है:

$$Y = 25 + 0.75 \times 175 + 75 = ₹\ 231 \text{ करोड़}$$

इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती हुई जब आय ₹ 400 करोड़ हो जायेगी तो कुल माँग भी ₹ 400 करोड़ होगी तथा बचत भी ₹ 75 करोड़ हो जायेगी जो निवेश के बराबर होगी। अतएव ₹ 400 करोड़ को संतुलित आय कहा जायेगा। क्योंकि इस स्तर पर दो शर्तें पूरी हो रही है।

(1) कुल पूर्ति (AS) तथा कुल माँग (AD) बराबर है।

(2) नियोजित निवेश तथा नियोजित बचत बराबर है। (Ex-ante Investment and Ex-ante Savings are equal.)

आय के निर्धारण को निम्नलिखित तालिका 2 तथा चित्र 3 की सहायता से सिद्ध किया जा सकता है।

5

केन्ज़ का रोज़गार सिद्धान्त

(KEYNESIAN THEORY OF EMPLOYMENT)

◆1. केन्ज़ का रोज़गार सिद्धान्त क्या है? (What is Keynesian Theory of Employment ?)

बीसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री **लार्ड जे० एम० केन्ज़** ने अपनी पुस्तक 'The General Theory of Employment, Interest and Money' (1936) में रोज़गार के आधुनिक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। **लार्ड केन्ज़** के अनुसार एक पूँजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोज़गार की स्थिति सामान्य स्थिति नहीं है। वास्तव में हर अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी पाई जा सकती है। **लार्ड केन्ज़** के ये विचार 1930 की महामंदी के अनुभव पर आधारित थे। सन् 1930 में लगभग सभी पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में महामंदी के कारण बेरोज़गारी में बहुत वृद्धि हुई थी। बेरोज़गारी का मुख्य कारण कुल पूर्ति की तुलना में कुल माँग में होने वाली कमी थी। कई देशों जैसे-अमेरिका, फ्रांस आदि ने बेरोज़गारी को दूर करने के लिए परंपरावादी रोज़गार सिद्धान्त द्वारा प्रतिपादित उपायों जैसे नकद मजदूरी में कटौती, ब्याज में कमी आदि को अपनाया। परन्तु इन उपायों द्वारा बेरोज़गारी दूर करने में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। **लार्ड केन्ज़** ने बेरोज़गारी की इस समस्या का वास्तविक विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला कि बेरोज़गारी का मुख्य कारण प्रभावपूर्ण माँग में होने वाली कमी है। प्रभावपूर्ण माँग कुल माँग का वह स्तर है जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होती है। इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया था कि **प्रभावपूर्ण माँग** (Effective Demand) को बढ़ाकर बेरोज़गारी को दूर किया जा सकता है। कुल माँग में दो प्रकार की माँग शामिल होती है। (1) **उपभोग वस्तुओं की माँग** (Consumption) तथा (2) **पूँजीगत वस्तुओं की माँग** (Investment)। अल्पकाल में उपभोग लगभग स्थिर रहता है। इसलिए प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि मुख्य रूप से निवेश में वृद्धि करके की जा सकती है। मंदी के दिनों में लाभ की संभावना कम होती है। इसलिए निजी क्षेत्र निवेश को अधिक नहीं बढ़ाएगा। अतएव् पूर्ण रोज़गार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह कार्य सरकार को करना पड़ेगा। **लार्ड केन्ज़** का यह विचार था कि बेरोज़गारी को दूर करके पूर्ण रोज़गार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए **सरकारी हस्तक्षेप** (Government Interference) आवश्यक है। **लार्ड केन्ज़** से पूर्व प्रसिद्ध परंपरावादी अर्थशास्त्री **माल्थस** (R.T. Malthus) ने भी यह मत प्रस्तुत किया था कि रोज़गार में कमी होने का मुख्य कारण प्रभावपूर्ण माँग में होने वाली कमी है। लेकिन माल्थस यह नहीं बता सके कि प्रभावपूर्ण माँग में कमी क्यों होती है।

◆2. मान्यताएँ (Assumptions)

लार्ड **केन्ज़** द्वारा प्रतिपादित रोज़गार का सिद्धान्त निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है:

(1) **अल्पकाल** (Short Period): **केन्ज़** का रोज़गार सिद्धान्त अल्पकाल में लागू होता है। लार्ड **केन्ज़** की यह मान्यता थी कि विकसित देशों में बेरोज़गारी की समस्या एक अल्पकालीन समस्या है क्योंकि, **"दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं।"** (In the long run we are all dead.) अल्पकाल में कुल पूर्ति स्थिर रहती है। अतएव कुल माँग में वृद्धि करके ही बेरोज़गारी को दूर करके रोज़गार की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है।

(2) पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect Competition): **केन्ज़** का रोज़गार सिद्धान्त भी परंपरावादी सिद्धान्त के समान पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है।

(3) बन्द अर्थव्यवस्था (Closed Economy): **केन्ज़** के रोज़गार सिद्धान्त की यह मान्यता है कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था बन्द अर्थव्यवस्था होती है जिसमें रोज़गार तथा आय के स्तर पर विदेशी व्यापार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(4) सरकारी आय तथा व्यय की उपेक्षा (Ignores the role of Government as a Spender or a Taxer): **केन्ज़** का सामान्य सिद्धान्त इस बात की उपेक्षा करता है कि सरकार का कोई **कार्य कर अधिकारी** (Taxer) या **व्ययकर्ता** (Spender) के रूप में है। **केन्ज़** ने कुल माँग पर सरकारी क्षेत्र के पड़ने वाले प्रभाव की अवहेलना की है।

(5) घटती सीमान्त उत्पादकता (Diminishing Marginal Productivity): **केन्ज़** के रोज़गार सिद्धान्त की एक मान्यता यह भी है कि जैसे-जैसे श्रम की अधिक इकाइयों को रोज़गार प्रदान किया जाता। उनकी सीमान्त उत्पादकता कम होती जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन पर **घटते सीमान्त प्रतिफल का नियम** (Law of Diminishing Marginal Returns) लागू होता है।

(6) केवल श्रम ही उत्पादन का घटता-बढ़ता साधन है (Labour is the only Variable Factor of Production): **केन्ज़** के सिद्धान्त की यह भी मान्यता है कि अल्पकाल में केवल श्रम ही उत्पादन का घटता-बढ़ता साधन है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करने से उत्पादन में वृद्धि होती है।

(7) श्रमिकों में मुद्रा भ्रान्ति है (Labour has Money Illusion): **केन्ज़** के रोज़गार सिद्धान्त की एक मान्यता यह भी है कि श्रमिकों में इस संबंध में गलतफहमी है कि मुद्रा की कीमत स्थिर रहती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि **श्रमिक** यह मानते हैं कि नकद मजदूरी जिस अनुपात में बढ़ेगी वास्तविक मजदूरी भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। श्रमिक कीमत में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की अवहेलना करता है।

(8) मुद्रा द्वारा मूल्य का संचय भी किया जाता है (Money also acts as a Store of Value): **केन्ज़** के सिद्धान्त की यह भी मान्यता है कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य ही नहीं करती बल्कि इसके द्वारा मूल्य का संचय भी किया जाता है।

(9) समय विलम्ब की उपेक्षा (No Time Lag): **केन्ज़** के सिद्धान्त की यह मान्यता है कि विभिन्न आर्थिक तत्त्वों में समन्वय (Adjustment) बिना किसी विलम्ब के होता है। आय में जिस अवधि में वृद्धि होती है उपभोग तथा निवेश में उसी अवधि मे परिवर्तन आ जाता है।

(10) अपूर्ण रोज़गार संतुलन (Under employment Equilibrium): **केन्ज़** के रोज़गार सिद्धान्त की एक मान्यता यह भी है कि संतुलन की स्थिति अपूर्ण रोज़गार की अवस्था में भी संभव है।

(11) बचत तथा निवेश फलन (Saving and Investment Function): **केन्ज़** का रोज़गार सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि बचत आय पर निर्भर करती है अर्थात् $S = f(Y)$। इसके विपरीत निवेश ब्याज की दर पर निर्भर करता है अर्थात् $I = f(r)$।

(12) ब्याज मौद्रिक तत्त्वों पर निर्भर करता है (Interest is a Monetary Phenomenon): **केन्ज़** के सिद्धान्त की यह भी मान्यता है कि ब्याज का निर्धारण मौद्रिक तत्वों अर्थात् मुद्रा की माँग तथा पूर्ति पर निर्भर करता है। मुद्रा की माँग, **तरलता अधिमान** (Liquidity Preference) द्वारा प्रकट की जाती है। तरलता अधिमान लेन-देन, सावधानी तथा सट्टा उद्देश्यों पर निर्भर करता है।

◆3. केन्ज़ के सिद्धान्त की व्याख्या (Explanation of Keynesian Theory)

लॉर्ड **केन्ज़** के रोजगार सिद्धान्त के अनुसार पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में कुल उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय रोज़गार के स्तर पर निर्भर करती है क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधन जैसे पूँजी, तकनीक आदि स्थिर रहते हैं। रोज़गार का स्तर प्रभावपूर्ण माँग पर निर्भर करता है। **प्रभावपूर्ण माँग** (Effective Demand) **कुल माँग के उस स्तर को कहते हैं जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होती है।** अतएव **एक्ले गार्डनर** के अनुसार **केन्ज़** के सिद्धान्त का आधारभूत विचार यह है कि किसी देश में रोजगार का स्तर कुल माँग तथा कुल पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। **प्रभावपूर्ण माँग** (Effective Demand) कुल माँग तथा कुल पूर्ति के संतुलन को प्रकट करती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कुल माँग के केवल उस स्तर को प्रभावपूर्ण माँग कहा जायेगा जिस पर वह देश में की जाने वाली कुल पूर्ति के बराबर हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी देश के एक लाख लोगों को रोज़गार पर लगाने से यदि एक निश्चित